

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 31-10-2025

विषय सूची

- » सरदार पटेल का दृष्टिकोण और राष्ट्रीय एकता का अर्थ
- » सभी स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा
- » अमेरिका-चीन बैठक
- » चाबहार बंदरगाह पर भारत को अमेरिकी छूट
- » भारत द्वारा वित्त वर्ष 2026 तक रिकॉर्ड 6 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य

संक्षिप्त समाचार

- » न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
- » साइप्रस IMEC का हिस्सा बनने के लिए तैयार
- » अमेरिका-चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों पर समझौता
- » लार्ज मैगैलैनिक क्लाउड (LMC)
- » नौरादेही अभयारण्य
- » अभ्यास त्रिशूल

सरदार पटेल का दृष्टिकोण और राष्ट्रीय एकता का अर्थ

संदर्भ

- 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस (Rashtriya Ekta Diwas) मनाया, जो सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।

सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में

- जन्म:** 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में लेउवा पटेल पाटीदार समुदाय में।
- शिक्षा:** कानून स्नातक, बाद में इंग्लैंड जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बने। भारत लौटने के बाद अहमदाबाद, गुजरात में वकालत शुरू की।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान

- सरदार पटेल ने अक्टूबर 1917 में महात्मा गांधी से भेंट की, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया।
- उन्होंने 1917 में अहमदाबाद के स्वच्छता आयुक्त के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और बाद में नगरपालिका समिति के अध्यक्ष (1924–1928) के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल होकर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध गुजरात में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया।
- बाद में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में सक्रिय भूमिका निभाई और गांधीजी के साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए जनसमर्थन जुटाया।

सरदार पटेल और सत्याग्रह

- खेड़ा सत्याग्रह (1918):** यह आंदोलन फसल की भारी बर्बादी के बाद भूमि राजस्व की माफी की मांग को लेकर शुरू हुआ।
 - तीन महीने तक चले शांतिपूर्ण आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को राहत देने पर बाध्य कर दिया, हालांकि इस दौरान गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती जैसी कठोर कार्रवाई हुई।

- बारडोली सत्याग्रह (1928):** जब ब्रिटिश अधिकारियों ने भूमि राजस्व में 22% से 60% तक की वृद्धि की, तब सरदार पटेल ने किसानों के प्रतिरोध का नेतृत्व अनुशासन और एकता के साथ किया।
 - इस आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें 'सरदार' की उपाधि दी, जिससे वे भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता और संगठित प्रतिरोध के प्रतीक बन गए।

राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार (स्वतंत्रता के पश्चात)

- सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने।
- उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करना था।
- भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उन्हें भारतीय सेना का वास्तविक सर्वोच्च सेनापति माना गया।
- उनकी दूरदृष्टि बाद के कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों में साकार हुई — गोवा का विलय (1961), सिक्किम का भारत में विलय (1975), और अनुच्छेद 370 का निरसन (2019), जिससे उनके पूर्ण एकता के स्वप्न की पूर्ति हुई।

सरदार पटेल की विरासत

- भारत के लौह पुरुष:** सरदार पटेल का जीवन दृढ़ संकल्प, एकता और नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण था। 'विविधता में एकता' में उनकी गहरी आस्था और समान उद्देश्य के लिए उनका नेतृत्व उन्हें भारत का लौह पुरुष बनाता है।
 - राष्ट्रीय एकता दिवस की स्थापना 2014 में की गई थी, ताकि स्वतंत्रता के पश्चात 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में उनके ऐतिहासिक योगदान को स्मरण किया जा सके।
- सम्मान और भारत रत्न पुरस्कार:** सरदार पटेल को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 1991 में मरणोपरान्त प्रदान किया गया — उनकी मृत्यु के 41 वर्ष बाद।

- सरदार पटेल की विरासत यह सिखाती है कि एकता जन्मजात नहीं होती — प्रत्येक पीढ़ी को इसे पुनर्निर्मित करना होता है। यह उदासीनता, अज्ञानता और क्षेत्रीयता जैसी शक्तियों के विरुद्ध सतत रक्षा की मांग करती है।
 - ▲ जैसे-जैसे भारत विकसित और विविध होता है, पटेल का संदेश प्रासंगिक बना रहता है: हमारी शक्ति समानता में नहीं, बल्कि एकजुटता में है।
- पटेल की एकता की कल्पना संघवाद पर आधारित थी — एक ऐसा संघ जो साझा विरासत से जुड़े मन और दिलों का मेल हो।

Source: TH

सभी स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा

संदर्भ

- हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि आगामी शैक्षणिक सत्र (2026-27) से कक्षा 3 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

परिचय

- विभाग CBSE, NCERT, KVS और NVS जैसे संस्थानों के साथ-साथ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान कर रहा है।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के व्यापक दायरे में एक सार्थक और समावेशी पाठ्यक्रम तैयार करना।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संगणनात्मक चिंतन (AI & CT) सीखने, सोचने एवं पढ़ाने की अवधारणाओं को सुदृढ़ करेगा, तथा धीरे-धीरे “जनहित के लिए AI” की दिशा में विस्तार करेगा।
- **प्रशिक्षण:** NISHTHA एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से शिक्षकों को कक्षा-विशिष्ट और समयबद्ध प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- **संसाधन सामग्री:** दिसंबर 2025 तक संसाधन सामग्री, पुस्तिकाएं और डिजिटल संसाधनों का विकास किया जाएगा।

- NCERT और CBSE के बीच समन्वय समिति के माध्यम से सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे एकीकृत संरचना और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

समर्थन में तर्क

- **AI साक्षरता की प्रारंभिक नींव:** प्रारंभिक स्तर पर परिचय बच्चों को AI की कार्यप्रणाली, क्षमताओं और सीमाओं को समझने में सहायता करता है।
 - ▲ AI से प्रभावित विश्व में, AI साक्षरता उतनी ही आवश्यक हो जाती है जितनी डिजिटल या वित्तीय साक्षरता।
- **भविष्य की कार्यशक्ति के लिए तैयारी:** AI की अवधारणाओं, उपकरणों और अनुप्रयोगों की समझ दीर्घकालिक रूप से रोजगार की संभावनाएं बढ़ा सकती है।
- **शिक्षा को अधिक रोचक और व्यक्तिगत बनाना:** AI उपकरण शिक्षा को वैयक्तिकृत कर सकते हैं — व्यक्तिगत सीखने की खामियों की पहचान, संसाधनों की सिफारिश, और अनुकूल प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं।
- **डिजिटल और सामाजिक अंतर का समापन:** यदि समावेशी पहुंच और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए तो संरचित AI शिक्षा असमानताओं को कम कर सकती है।
- **मूलभूत मानवीय कौशल को सुदृढ़ करना:** यदि सही मार्गदर्शन मिले तो AI आधारित शिक्षा समस्या-समाधान, रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ा सकती है, न कि उन्हें प्रतिस्थापित कर सकती है।

विरोध में तर्क

- **तेजी से बदलती तकनीक:** AI तकनीक इतनी तीव्रता से विकसित हो रही है कि शैक्षणिक प्रणाली उसके अनुरूप नहीं हो पा रही।
 - ▲ हजारों स्कूलों में AI पाठ्यक्रम को नियमित रूप से डिजाइन और अपडेट करना प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण है।
- **डिजिटल और आधारभूत संरचना की कमी:** भारत के कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है — जैसे कंप्यूटर, विद्युत या इंटरनेट।

- ▲ इन खामियों को दूर किए बिना AI शिक्षा शुरू शैक्षणिक असमानताओं को बढ़ाएगा, जिससे केवल शहरी या विशेषाधिकार प्राप्त छात्र लाभान्वित होंगे।
- **अप्रशिक्षित और पहले से ही बोझिल शिक्षक:** अधिकांश शिक्षक स्वयं AI साक्षर नहीं हैं और AI की अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।
 - ▲ बड़े पैमाने पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भारी निवेश और समय की मांग करेगा।
- **“अशिक्षा” और सीखने की प्रेरणा में कमी का जोखिम:** AI उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता छात्रों की जिज्ञासा और सीखने के प्रयास को कम कर सकती है।
 - ▲ इससे गहन सीखने, रचनात्मकता तथा आलोचनात्मक सोच का क्षरण हो सकता है, और प्रयास की जगह शॉर्टकट ले सकते हैं।
- **अप्रमाणित और पक्षपाती तकनीक:** AI प्रणाली प्रायः पक्षपाती या अधूरी जानकारी पर प्रशिक्षित होती हैं, जिससे अविश्वसनीय या भेदभावपूर्ण परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
 - ▲ बच्चों को ऐसी प्रणालियों पर निर्भर रहने देना उनकी समझ को विकृत कर सकता है और रूढ़ियों को सुदृढ़ कर सकता है।

आगे की राह

- **चरणबद्ध और आयु-उपयुक्त मॉडल अपनाना:** प्रारंभिक कक्षाओं में AI साक्षरता पर ध्यान दें, और उच्च कक्षाओं में AI कौशल (कोडिंग, डेटा उपयोग) पर।
- **शिक्षकों और संरचना को सुदृढ़ करना:** डिजिटल साक्षरता और AI जागरूकता में निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करें।
- **नैतिकता और सुरक्षा उपायों का समावेश:** जिम्मेदार AI उपयोग, पक्षपात और डेटा गोपनीयता पर आधारित मॉड्यूल शामिल करें।

- ▲ स्कूलों में उपयोग किए जाने वाले AI उपकरणों के लिए बाल संरक्षण मानदंड और सुरक्षा उपाय लागू करें।
- **रचनात्मकता और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना:** AI का उपयोग समस्या-समाधान, नवाचार और सहयोग को बढ़ाने के लिए करें — प्रयास के विकल्प के रूप में नहीं।
 - ▲ छात्रों को तकनीक-प्रेरित भविष्य के लिए अनुकूलनशीलता और सतत सीखने की मानसिकता विकसित करने के लिए तैयार करें।

Source: TH

अमेरिका-चीन बैठक

संदर्भ

- दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिका और चीन के बीच हुए शिखर सम्मेलन का समापन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई परिणामों के साथ हुआ।

मुख्य निष्कर्ष

- अमेरिका ने चीन पर लगाए गए शुल्क को घटाकर 47% कर दिया है, जिससे भारत (और ब्राजील) 50% के साथ सबसे अधिक शुल्क वाला देश बन गया है।
- चीन ने एक वर्ष की अवधि के समझौते के अंतर्गत विश्व को दुर्लभ खनिजों (जो वैश्विक उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोग होते हैं) का निर्यात जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है।

शिखर सम्मेलन का महत्व

- **G-2:** अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बैठक को “G-2” कहा, जो G-20 और G-7 जैसे समूहों से प्रेरित है, जिनमें विश्व की कुछ सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
 - ▲ चीन के लिए यह स्वीकार्यता उसकी शक्ति की स्थिति की मान्यता थी।
 - ▲ किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से चीन की स्थिति को इस रूप में स्वीकार नहीं किया था, जिससे यह बीजिंग के लिए एक बड़ी जीत बन गई।

G-2 की अवधारणा

- G-2 या अमेरिका-चीन के विशेष क्लब की अवधारणा को वैश्विक मुद्दों पर कार्य करने के लिए लगभग 15 वर्ष पहले 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा एवं चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ के बीच हुए शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
- उस समय व्यापार, जलवायु परिवर्तन और परमाणु प्रसार अमेरिका के लिए प्रमुख चिंताएं थीं।
 - ▲ बाद में अमेरिका-चीन तनाव बढ़ने के साथ, प्रशासन ने 2011 तक इस विचार को पूरी तरह से छोड़ दिया।

- **अमेरिकी राष्ट्रपति का दृष्टिकोण:** विश्व के कुछ नेताओं के साथ पूर्ववर्ती बातचीत को देखते हुए, चीनी राष्ट्रपति के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति का सहमति-पूर्ण दृष्टिकोण विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से निपटने में सीमाओं का संकेत था।
- **दुर्लभ खनिजों पर प्रतिबंध में देरी:** शिखर सम्मेलन से संकेत मिलता है कि अमेरिका चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे को टालने में सफल रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति पर चीन की पकड़ को देखते हुए एक महत्वपूर्ण चिंता थी।

दुर्लभ खनिज

- दुर्लभ खनिजों का समूह 17 धात्विक तत्वों से बना होता है, जिनका उपयोग मैग्नेट और अन्य घटकों के निर्माण में होता है — जो मिसाइलों, विमानों, कारों एवं रेफ्रिजरेटर जैसे उत्पादों के निर्माण में अनिवार्य हैं।
- शुल्क युद्ध के बीच, चीन ने अपने निर्यात पर सीमाएं लगाकर अपनी प्रभावशाली स्थिति को दर्शाया, जिससे वैश्विक उद्योग प्रभावित हुए।

भारत के लिए प्रभाव

- **QUAD की प्रासंगिकता:** यह अनिश्चितता क्वाड की प्रासंगिकता और भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगाती है — यह वह रणनीतिक ढांचा है जिसमें भारत अमेरिका, जापान

एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करता है।

- **भारत पर शुल्क:** चीन पर शुल्क घटाकर 47% कर दिए गए हैं, जिससे भारत अब प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक 50% शुल्क वाला देश बन गया है।
 - ▲ इससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को तीव्र करने का दबाव बढ़ता है।
- “G-2” शब्द का प्रयोग अमेरिका-चीन के बीच संभावित समन्वय का संकेत देता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है — क्योंकि भारत बहुध्रुवीयता का समर्थक है, न कि द्विध्रुवीय या साझा प्रभुत्व का।
 - ▲ G-2 ढांचा वैश्विक प्रभाव को “प्रभाव क्षेत्रों” में विभाजित कर सकता है, जिससे भारत की स्वतंत्र भूमिका को चुनौती मिल सकती है।

आगे की राह

- भारत को इस शक्ति समीकरण के आलोक में अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि रणनीतिक स्वायत्तता बनी रहे।
 - ▲ अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग, बाजार पहुंच और निवेश, इंडो-पैसिफिक समुद्री सुरक्षा के लिए जुड़ाव बढ़ाना चाहिए।
 - ▲ चीन के साथ व्यापार और क्षेत्रीय आर्थिक ढांचे में जहां हित समान हों — जलवायु, अवसंरचना और बहुपक्षीय कूटनीति — वहां व्यावहारिक रूप से जुड़ना चाहिए।
 - ▲ जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ASEAN और यूरोपीय साझेदारों (फ्रांस, EU) के साथ साझेदारी को गहरा करना चाहिए ताकि रणनीतिक विकल्पों का विविधीकरण हो सके।
- भारत की बाह्य प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए घरेलू आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है।

Source: TH

चाबहार बंदरगाह पर भारत को अमेरिकी छूट

संदर्भ

- भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिका के प्रतिबंधों से छह महीने की छूट प्राप्त हुई है।

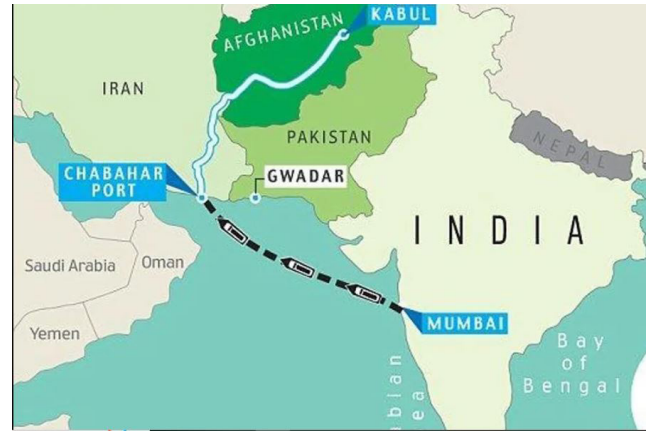
पृष्ठभूमि

- भारत और ईरान ने 2015 में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे ताकि चाबहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह का संयुक्त रूप से विकास किया जा सके।
- उद्देश्य:** एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र का विकास करना, जिससे भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशियाई देशों और रूस के बाजारों तक पहुंच मिल सके।
- प्रतिबंध:** पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह की संभावनाएं प्रभावित हुईं, लेकिन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय गतिविधियों को छूट दी।
 - 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद चाबहार परियोजना से जुड़े किसी भी पक्ष को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।

चाबहार बंदरगाह

- ईरान का चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित है और देश का एकमात्र महासागरीय बंदरगाह है।
- यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के चाबहार शहर में स्थित है।
- चाबहार में दो बंदरगाह हैं: शाहिद कलांतरी और शाहिद बेहेस्ती।
 - शाहिद कलांतरी एक प्राचीन बंदरगाह है, जिसकी जलसीमा सीमित है और यह केवल छोटे जहाजों को समायोजित कर सकता है।
 - शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह को चार चरणों में विकसित किया जा रहा है। सभी चरणों के पूर्ण होने पर इसकी क्षमता 82 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी।
- यह बंदरगाह ऊर्जा-समृद्ध फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट तक पहुंच प्रदान करता है और पाकिस्तान को दरकिनार करता है।

- गुजरात का कांडला बंदरगाह सबसे निकटतम है, जिसकी दूरी 550 नॉटिकल मील है, जबकि चाबहार और मुंबई के बीच की दूरी 786 नॉटिकल मील है।



भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व

- भू-राजनीतिक महत्व:** यह दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के संगम पर रणनीतिक रूप से स्थित है। यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक समुद्री मार्ग से सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान को दरकिनार किया जा सकता है।
 - यह बंदरगाह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान के बीच माल परिवहन संभव होता है। यह विविधता भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करती है।
- INSTC का प्रवेश द्वार:** चाबहार बंदरगाह भारत को ईरान तक पहुंच प्रदान करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का प्रमुख प्रवेश द्वार है। यह गलियारा भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच समुद्री, रेल एवं सड़क मार्गों से जुड़ा है।
- चीन का सामना:** चाबहार बंदरगाह भारत को अरब सागर में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने में सहायता करता है, जहां चीन पाकिस्तान को ग्वादर बंदरगाह के विकास में सहायता देकर अपनी पकड़ सुदृढ़ कर रहा है।
- व्यापारिक लाभ:** चाबहार बंदरगाह के कार्यशील होने से भारत में लौह अयस्क, चीनी और चावल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

- भारत में तेल के आयात की लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

Source: TH

भारत द्वारा वित्त वर्ष 2026 तक रिकॉर्ड 6 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य

पाठ्यक्रम: GS3/ ऊर्जा

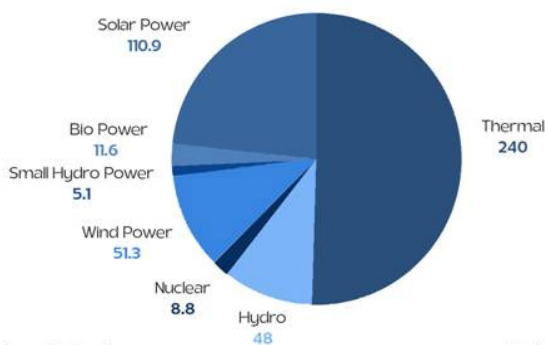
संदर्भ

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 6 गीगावाट (GW) नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी जाएगी।

भारत में पवन ऊर्जा

- भारत वर्तमान में विश्व में चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 51.67 GW है (12 अगस्त 2025 तक), जिसमें से 4.15 GW वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जोड़ी गई।
- पवन ऊर्जा ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच 78.21 बिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की, जो देश में कुल विद्युत उत्पादन का 4.69% है।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अनुसार, देश की अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता 1,164 GW है, जो भूमि से 150 मीटर की ऊंचाई पर मापी गई है।

India's Installed Power Capacity Mix
(Numbers in Gigawatt)



Source: Ministry of power

As of June, 2025

पवन ऊर्जा का महत्व

- स्वच्छ ऊर्जा स्रोत:** पवन ऊर्जा संचालन के दौरान शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करती है, जिससे भारत

के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) और नेट जीरो 2070 लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

- ग्रामीण और तटीय विकास:** पवन ऊर्जा संयंत्र मुख्यतः ग्रामीण या तटीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जिससे बुनियादी ढांचे का विकास, स्थानीय रोजगार और सामुदायिक आय में वृद्धि होती है।
- सतत विकास:** दूरदराज के क्षेत्रों को बिजली प्रदान कर समावेशी विकास को समर्थन देना।
 - स्वच्छ तकनीकों में नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करना।
 - तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए ऊर्जा की बढ़ती मांग को सतत रूप से पूरा करना।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को 2022 में प्रस्तुत अद्यतन NDC के अंतर्गत:
 - भारत ने 2030 तक अपने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 45% तक कम करने का संकल्प लिया है।
 - 2030 तक कुल विद्युत शक्ति क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य है।
 - 'LIFE' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) आंदोलन के माध्यम से सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना।
- ये लक्ष्य भारत के दीर्घकालिक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य (2070) में भी योगदान करते हैं।
- राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की परिकल्पना करती है, जिसमें सौर ऊर्जा से 50% योगदान की अपेक्षा है।

भारत में पवन ऊर्जा की चुनौतियाँ

- स्थल संबंधी सीमाएं:** उच्च पवन क्षमता वाले स्थल मुख्यतः कुछ राज्यों — तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र — में केंद्रित हैं, जिससे भौगोलिक विस्तार सीमित होता है।

- ▲ भूमि उपलब्धता, वन स्वीकृति और सामाजिक विरोध जैसी समस्याएं परियोजना समयसीमा को प्रभावित करती हैं।
- पवन ऊर्जा उत्पादन की अनियमितता ग्रिड स्थिरता को चुनौती देती है और इसके लिए ऊर्जा भंडारण एवं पूर्वानुमान प्रणाली में निवेश की आवश्यकता होती है।
- **नीतिगत अनिश्चितता:** निविदा दिशानिर्देशों, ऑफटेक तंत्र और RPO (नवीकरणीय खरीद दायित्व) लक्ष्यों में बार-बार परिवर्तित से अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
- **डेटा की कमी:** कई आंतरिक क्षेत्रों के लिए पवन संसाधन डेटा अभी भी अपर्याप्त या प्राचीन है।

सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन:** भारत में पवन ऊर्जा के विकास और विस्तार पर केंद्रित। 2030 तक पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 140 GW निर्धारित किया गया है।
- **घरेलू निर्माण और नीतिगत प्रोत्साहन:**
 - ▲ वर्तमान में भारत की पवन उद्योग में 70% स्थानीय सामग्री है। 2030 तक इसे 85% तक बढ़ाने का लक्ष्य है ताकि घरेलू निर्माण को सुदृढ़ किया जा सके।
 - ▲ **कर प्रोत्साहन:** पवन उपकरणों पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे प्रति MW टरबाइन लागत में लगभग ₹25 लाख की कमी आई है।
- **वैश्विक निर्माण महत्वाकांक्षा:** ALMM (स्वीकृत मॉडल और निर्माता सूची)-पवन ढांचे जैसी पहलों के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक पवन मांग का 10% और 2040 तक 20% पूरा करना है, जिससे भारत को टरबाइन और घटकों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 MW प्रत्येक के 1 GW अपतटीय पवन परियोजनाओं एवं बंदरगाह उन्नयन के लिए ₹7,453 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को स्वीकृति दी है।

आगे की राह

- पवन ऊर्जा संयंत्रों के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बैटरी और पंप्ड हाइड्रो) को एकीकृत करें ताकि निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- NIWE जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी में पवन तकनीक के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करें ताकि अपतटीय, हाइब्रिड और उन्नत टरबाइन डिजाइन में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- ग्रिड दक्षता और भूमि उपयोग को अधिकतम करने के लिए पवन, सौर और भंडारण को मिलाकर हाइब्रिड निविदाओं को बढ़ावा दें।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

समाचार में

- न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वे 24 नवंबर 2025 को कार्यभार संभालेंगे। वे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी होंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- मुख्य न्यायाधीश सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं जिन्हें इस पद के लिए उपयुक्त माना जाता है।
 - ▲ केंद्रीय विधि मंत्री निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अनुशंसा प्राप्त करते हैं, जिसे प्रधानमंत्री को भेजा जाता है, जो राष्ट्रपति को अंतिम नियुक्ति के लिए परामर्श देते हैं।
- अन्य न्यायाधीशों के लिए, कॉलेजियम उम्मीदवारों की सिफारिश करता है, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीशों की लिखित राय शामिल होती है।

योग्यता

- इस पद के लिए पात्रता हेतु व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करनी चाहिए:
 - ▲ कम से कम पाँच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक उच्च न्यायालयों में क्रमिक रूप से न्यायाधीश रहे हों।
 - ▲ कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहे हों।
 - ▲ राष्ट्रपति द्वारा एक विशिष्ट विधिवेत्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हों।

क्या आप जानते हैं?

- अनुच्छेद 217, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, कहता है कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए।
 - ▲ इसके अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

प्रक्रिया

- भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- हालाँकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है, यह प्रणाली प्रथम और तृतीय न्यायाधीश मामलों जैसे प्रमुख निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई, जिससे नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्थानांतरित हो गई।
- सरकार पृष्ठभूमि जांच कर सकती है और आपत्तियाँ उठा सकती है, लेकिन सामान्यतः कॉलेजियम का निर्णय ही मान्य होता है।
 - ▲ वरिष्ठता ही प्रमुख मानदंड होती है, और विधि मंत्री कॉलेजियम की सिफारिश को प्रधानमंत्री को भेजते हैं, जो राष्ट्रपति को अंतिम नियुक्ति के लिए परामर्श देते हैं।

Source :TH

साइप्रस IMEC का हिस्सा बनने के लिए तैयार

समाचार में

- साइप्रस के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया और भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे (IMEC) में शामिल होने की तत्परता दिखाई। उन्होंने साइप्रस की रणनीतिक स्थिति, यूरोपीय संघ की सदस्यता और मजबूत नौवहन क्षेत्र को इसका आधार बताया।

साइप्रस के बारे में

- यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, जो अपने समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है।



- यह तुर्की के दक्षिण में लगभग 40 मील और सीरिया के पश्चिम में लगभग 60 मील की दूरी पर स्थित है।
- यह 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, लेकिन ग्रीक और तुर्की साइप्रसियों के बीच तनाव के कारण 1974 से एक वास्तविक विभाजन की स्थिति बनी हुई है।

भारत के साथ सहयोग

- भारत और साइप्रस गणराज्य (RoC) के बीच छह दशकों से अधिक समय से सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंध हैं, जो मित्रता, पारस्परिक सम्मान एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग पर आधारित हैं।
 - ▲ 1962 में स्थापित संबंधों ने राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में विस्तार किया है।
- दोनों देश वैश्विक संगठनों में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं — भारत संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत साइप्रस के

पुनः एकीकरण का समर्थन करता है, जबकि साइप्रस भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता और असैन्य परमाणु पहलों का समर्थन करता है।

- दोनों पक्षों ने भारत-साइप्रस संयुक्त कार्य योजना (2025–2029) की समीक्षा की और क्षेत्रीय घटनाक्रमों व बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की, विशेष रूप से साइप्रस के 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने की तैयारी के संदर्भ में।
- साइप्रस ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते का भी समर्थन किया, और इसके माध्यम से प्रमुख आर्थिक अवसरों को खोलने की संभावना को रेखांकित किया।

भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा (IMEC)

- IMEC की घोषणा 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य “एशिया, अरब खाड़ी और यूरोप के बीच बेहतर संपर्क एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना” है।
- यह एक प्रस्तावित गलियारा है, जो जहाज, जहाज-रेल और सड़क नेटवर्क के माध्यम से भारत को खाड़ी क्षेत्र से तथा खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने का कार्य करेगा।

Source :TH

अमेरिका-चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों पर समझौता

समाचार में

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया में अपनी बैठक के बाद एक समझौते पर सहमति जताई, जिसके तहत चीन अमेरिका को दुर्लभ खनिजों का निर्यात बनाए रखेगा।

दुर्लभ खनिज तत्व क्या हैं?

- **सामान्य जानकारी:** “दुर्लभ” शब्द उनके निकासी योग्य भंडारों में कम सांद्रता को दर्शाता है, जिससे इनका खनन और प्रसंस्करण आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है।
- **प्रकार:** ये 17 धात्विक तत्वों का समूह हैं, जिनमें स्कैंडियम और यट्रियम भी शामिल हैं। ये उच्च घनत्व,

गलनांक, विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता के लिए जाने जाते हैं।

- **स्रोत:** ये मुख्य रूप से बैस्टनासाइट, लोपाराइट और मोनाज़ाइट से प्राप्त होते हैं, तथा परमाणु क्रमांक के आधार पर हल्के (सेरियम समूह) एवं भारी (यट्रियम समूह) वर्गों में विभाजित किए जाते हैं।
- **वितरण:** चीन वैश्विक दुर्लभ खनिज बाजार में अग्रणी है — यह 60% खनन उत्पादन और 90% से अधिक परिष्कृत उत्पादों व मैग्नेट का उत्पादन करता है।
- **उपयोग:** ये अत्यंत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, रक्षा प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा और चिकित्सा उपकरणों जैसी उन्नत तकनीकों के लिए आवश्यक होते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** दुर्लभ खनिजों का प्रसंस्करण विषैले रसायनों पर निर्भर करता है, जो मृदा, वायु और जल को प्रदूषित कर सकते हैं।
 - ▲ कई अयस्कों में थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व भी होते हैं, जिनके लिए अम्लीय उपचार की आवश्यकता होती है, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं।
 - ▲ हालांकि स्वच्छ निष्कर्षण विधियाँ उपलब्ध हैं, वे महंगी हैं और व्यापक रूप से उपयोग नहीं होतीं, जिससे मांग को पूरा करने तथा पर्यावरणीय क्षति को कम करने के बीच टकराव उत्पन्न होता है।

भारत की स्थिति और कदम

- भारत के पास विश्व में तीसरे सबसे बड़े दुर्लभ खनिज तत्वों (REEs) के भंडार हैं, जिनका अनुमान 6.9 मिलियन मीट्रिक टन है।
- ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और केरल में पाए जाते हैं, जिनमें केरल की मोनाज़ाइट रेत विशेष रूप से समृद्ध है।
- सरकार ने 2023 में खनिज और खनन अधिनियम में संशोधन कर REEs को “महत्वपूर्ण खनिज” के रूप में वर्गीकृत किया तथा 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की।

Source :IE

लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC)

संदर्भ

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC) में ST6 नामक एक नवजात तारे के चारों ओर पाँच कार्बन-समृद्ध यौगिकों की पहचान की।

लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC) के बारे में

- LMC मिल्की वे की एक बौनी अनियमित उपग्रह आकाशगंगा है, जो पृथ्वी से लगभग 1,60,000 प्रकाश-वर्ष दूर डोराडो तारामंडल में स्थित है।
- संरचना:** यह अपनी विशाल, चमकदार नीहारिकाओं के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि टारेंटुला नीहारिका, जो सक्रिय तारों की उत्पत्ति का संकेत देती हैं।
- तारों की संख्या:** इसमें लगभग 30 अरब तारे हैं, जिनमें कई युवा और तारा-निर्माण क्षेत्र शामिल हैं।
- संघटन:**
 - LMC में मिल्की वे की तुलना में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों की मात्रा कम है।
 - इस प्रकार की धातु-गरीब स्थितियाँ प्रारंभिक ब्रह्मांड की परिस्थितियों की नकल करती हैं, जिससे यह आदिम ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला बन जाती है।

Source: IE

नौरादेही अभयारण्य

संदर्भ

- नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद भारत में चीता संरक्षण के लिए तीसरा स्थान बनने जा रहा है।

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और सागर तथा दमोह जिलों में फैले एक पठार पर स्थित है।
- यह साल, सागौन, महुआ, बांस और बेल जैसे पर्णपाती वनों की विशेषता वाला क्षेत्र है।

- यहां विस्तृत घास के मैदान हैं जो चिंकारा, जंगली सूअर और अन्य शाकाहारी जीवों सहित एक सुदृढ़ शिकार आधार का समर्थन करते हैं।

प्रोजेक्ट चीता क्या है?

- प्रोजेक्ट चीता भारत का चीता पुनर्स्थापन कार्यक्रम है।
 - इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के एकमात्र विलुप्त बड़े स्तनधारी — चीता — को वापस लाना है।
- भारत सरकार ने 1952 में आधिकारिक रूप से चीते को विलुप्त घोषित किया था।
- प्रथम समूह, जिसमें आठ चीते शामिल थे, 2022 में नामीबिया से आया था और दूसरा समूह, जिसमें 12 चीते थे, 2023 में दक्षिण अफ्रीका से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया।
- 2025 में दो नर चीते कुनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किए गए, जिससे यह प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत भारत में चीतों का दूसरा आवास बन गया।

Source: THE PRINT

अभ्यास त्रिशूल

संदर्भ

- भारत ने त्रिशूल अभ्यास 2025 की शुरुआत की है, जो गुजरात और राजस्थान में आयोजित एक प्रमुख त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास है, जिसमें थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना शामिल हैं।

अभ्यास के बारे में

- त्रिशूल अभ्यास 2025 ऑपरेशन सिंदूर हमलों के छह महीने बाद अब तक का सबसे बड़ा त्रि-सेवा अभ्यास है।
- गुजरात के कच्छ क्षेत्र, जो सर क्रीक सीमा के पास स्थित है — और जो पाकिस्तान के साथ लंबे समय से तनाव का केंद्र रहा है — इस अभ्यास का मुख्य संचालन क्षेत्र है।
- 20,000 से अधिक सैनिक, T-90S और अर्जुन टैंकों, अटैक हेलीकॉप्टरों, मिसाइल प्रणालियों, राफेल और सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों, साथ ही फ्रिगेट्स एवं विध्वंसक जहाजों के बेड़े की सहायता से पश्चिमी मोर्चे पर संयुक्त अभियान चला रहे हैं।

Source: IT